

2024

1. राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (1) हरिभाऊ किसनराव बागडे, ने 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला।
- (2) राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया।
- (3) 7वें संविधान संशोधन से राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया।
- (4) गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[4]

व्याख्या:-

- 25 अक्टूबर, 1956 गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

2. निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया?

- (1) शिवचरण माथुर
- (2) हरिदेव जोशी
- (3) भैरोंसिंह शेखावत
- (4) जयनारायण व्यास
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[3]

व्याख्या:-

- राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत ने अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया।
- राजस्थान में अब तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

राष्ट्रपति शासन	वर्ष	मुख्यमंत्री
1. पहला	1967	मोहनलाल सुखाड़िया
2. दूसरा	1977	हरिदेव जोशी
3. तीसरा	1980	भैरोंसिंह शेखावत
4. चौथा	1992	भैरोंसिंह शेखावत

3. नवम्बर, 2024 के अंत तक, राजस्थान की मंत्रिपरिषद् में कितनी महिलाएँ थी?

- (1) केवल 5
- (2) केवल 1
- (3) केवल 2
- (4) केवल 3
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[3]

व्याख्या:-

- नवम्बर, 2024 के अंत तक, राजस्थान की मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers - भजन लाल शर्मा मंत्रिमंडल) में केवल 2 महिलाएँ थी। यह दो महिला मंत्री हैं: दीया कुमारी (उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री) तथा डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री)।

4. निम्नलिखित में से राजस्थान विधान सभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (1) यह राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है।
- (2) अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले

कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी "आदेशों" की जाँच करती है।

(3) समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जाँच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियाँ सौंपने की माँग करते हैं।

(4) अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है।

(5) अनुत्तरित प्रश्न

[1]

व्याख्या:-

- अधीनस्थ विधान समिति राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 183 (विशेष रूप से अध्याय 20, अधीनस्थ विधान) द्वारा शासित होती है, न कि नियम 240 द्वारा।

5. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है?

- (1) अनुच्छेद-325 (4)
- (2) अनुच्छेद-320(3)
- (3) अनुच्छेद-318 (1)
- (4) अनुच्छेद-322(2)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[2]

व्याख्या:-

- राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-320(3) के तहत है।

- संविधान का अनुच्छेद-320 लोक सेवा आयोगों (UPSC और SPSCs) के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद-320(3) विशेष रूप से यह उपबंध करता है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मामलों में परामर्श किया जाएगा-

- **अनुशासनात्मक मामले:** उन सभी अनुशासनात्मक मामलों पर जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत है। इसमें अनुशासनात्मक शास्तियों (penalties) से संबंधित मामले भी शामिल हैं। यह परामर्श आयोग के कार्य क्षेत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, हालाँकि आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है।

6. निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला?

- (1) 20/05/2024
- (2) 20/02/2024
- (3) 20/03/2024
- (4) 20/04/2024
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[4]

व्याख्या:-

- प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार 20 अप्रैल, 2024 को संभाला था।

7. राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है?

- (1) जिला प्रमुख
- (2) जिला कलक्टर
- (3) जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(4) संसद सदस्य

(5) अनुत्तरित प्रश्न [1]

व्याख्या:-

- जिला प्रमुख, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 35 के अनुसार, जिला परिषद् का अध्यक्ष होता है, और वह ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होता है।
- यह पद निर्वाचित प्रतिनिधियों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य या वह व्यक्ति होता है जो जिले में योजनाएँ बनाने और देखरेख का कार्य करता है।
- जिला आयोजना समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद-243ZD के तहत किया जाता है और यह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएँ बनाने का कार्य करती है।
- अध्यक्ष:** राजस्थान में, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख (जो जिला परिषद् का निर्वाचित मुखिया होता है) होता है।
- उपाध्यक्ष:** जिला कलेक्टर (District Collector) समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- उद्देश्य:** समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करके संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करना होता है।

8. किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी?

- (1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985
- (2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982
- (3) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1983
- (4) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1984
- (5) अनुत्तरित प्रश्न [2]

व्याख्या:-

- जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority - JDA) की स्थापना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के द्वारा हुई थी। यह अधिनियम 1982 में राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य जयपुर शहर के नियोजित विकास, भूमि उपयोग के विनियमन और नगरीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समन्वित और सर्वोच्च प्राधिकरण की स्थापना करना था। यह अधिनियम जयपुर नगर के शहरी विकास, योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के नियोजन, विकास और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है और जयपुर शहर के व्यवस्थित एवं समग्र विकास हेतु जिम्मेदार है।

9. निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था?

- (1) करौली, बूँदी, अलवर, जैसलमेर
- (2) अलवर, बाँसवाड़ा, करौली, सिरौही
- (3) बाँसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूँदी
- (4) जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरौही

(5) अनुत्तरित प्रश्न [4]

व्याख्या:-

- रियासती राज्यों का समूह- जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरौही ही एकमात्र ऐसा समूह है, जिसने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था।
- जयपुर (1937), उदयपुर (1940), जोधपुर (1945) और सिरौही (1947) ने क्रमशः अपने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किए। इन रियासतों में विधायी प्रगति प्रशासनिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दबाव (विशेषकर प्रजामंडल आंदोलनों से) और ब्रिटिश भारत में चल रहे संवैधानिक सुधारों के अनुकरण का एक जटिल मिश्रण थी।
- यह स्वाधीनता से पहले ही स्थानीय स्वशासन की संस्थागत नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आगे चलकर एकीकृत राजस्थान राज्य में पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन (1953 अधिनियम और 1959 के उद्घाटन) के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

10. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने पाँच वर्ष की पदावधि पूरी की?

- (1) न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया
- (2) न्यायमूर्ति श्रीमती कांता भटनागर
- (3) न्यायमूर्ति एन. के. जैन
- (4) न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
- (5) अनुत्तरित प्रश्न [3]

व्याख्या:-

- राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (RSHRC) के अध्यक्षों में से न्यायमूर्ति एन. के. जैन ने पाँच वर्ष (16-07-2005 से 15-07-2010) की पूरी पदावधि पूरी की।
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता था तथा अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं थी। 2019 के संशोधन के बाद, यह कार्यकाल अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया है तथा अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

11. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के तहत, लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जाँच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय उन जाँचों का हिस्सा नहीं है?

- (1) लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है।
- (2) लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा।
- (3) अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना।
- (4) महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न [4]

व्याख्या:-

- राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जाँच करने का अधिकार है। इन आरोपों में शामिल हैं:

- लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या पारदर्शिता की कमी से संबंधित दोष।
- लोक सेवकों द्वारा पहुँचाई गई अकारण हानि या पीड़ा।
- अपने या अन्य के लिए अवैध लाभ पाने हेतु आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना।
- लेकिन धारा 7 के अंतर्गत महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा का मामला लोकायुक्त की जाँच का हिस्सा नहीं है। ऐसे मामले अन्य कानूनों के तहत आते हैं।

12. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है ?

- (1) ₹40,000
- (2) ₹10,000
- (3) ₹20,000
- (4) ₹30,000

[4]

व्याख्या:-

- महापौर (Mayor) का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अमानत (या जमानत) राशि ₹30,000 निर्धारित की गई है।
- नोट:** यह राशि राज्य के नगर निकाय चुनावों के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

13. राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफ़ारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है ?

- (1) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- (2) मुख्यमंत्री
- (3) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता
- (4) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[1]

व्याख्या:-

- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफ़ारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं होता है।
- राज्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner - SCIC) और अन्य राज्य सूचना आयुक्तों (State Information Commissioners - SICs) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफ़ारिश पर की जाती है। यह समिति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अनुसार गठित होती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- मुख्यमंत्री (जो समिति का अध्यक्ष होता है)।
- राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता।
- मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री।

14. सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है-

- (1) जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
- (2) गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना
- (3) नागरिक उन्मुखी शासन
- (4) उत्तरदायी सरकार
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[1]

व्याख्या:-

- सिटिजन चार्टर (Citizen's Charter)** एक दस्तावेज़ है, जो किसी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने नागरिकों/ग्राहकों के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप देता है।
- यह आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित होता है-
- सेवा की गुणवत्ता और मानक (Quality and Standards):** गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability): उत्तरदायी सरकार।
- शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal):** चार्टर में शिकायत निवारण की प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन यह स्वयं "जनता की माँगों की सुनवाई का तंत्र" नहीं होता, बल्कि यह सेवा वितरण के संबंध में शिकायत निवारण पर केंद्रित होता है।
- सेवा उन्मुखता (Service Orientation):** नागरिक उन्मुखी शासन।
- जबकि सिटिजन चार्टर अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत निवारण के माध्यम से जनता की आवाज को सुनता है, इसका मुख्य उद्देश्य "जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना" नहीं है। माँगों की सुनवाई के लिए अलग संस्थागत मंच (जैसे जन सुनवाई, स्थानीय निकाय, आदि) मौजूद होते हैं। सिटिजन चार्टर का प्राथमिक ध्यान सेवा वितरण के मानक और समयबद्धता निर्धारित करना है।

2023

15. निम्न में से कौन-सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है?

- (1) मोहनलाल सुखड़िया ने चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- (2) वर्ष 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे।
- (3) बरकतुल्ला खाँ सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे।
- (4) सी.एस. वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

[3]

व्याख्या:-

- हीरा लाल देवपुरा सबसे कम अवधि 23 फरवरी, 1985 से 10 मार्च, 1985 तक मात्र 16 दिन के कार्यकाल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे।
- मोहनलाल सुखड़िया चार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल 13 नवम्बर, 1954 से 9 जुलाई, 1971 तक रहा।

16. राजस्थान की मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है?

- (1) 12 (2) 10
(3) 8 (4) 5
(5) अनुत्तरित प्रश्न [1]

व्याख्या:-

- राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 तक हो सकती है।
- 91वें संविधान संशोधन, 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

17. 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य का मत-मूल्य था-

- (1) 149 (2) 132
(3) 129 (4) 116
(5) अनुत्तरित प्रश्न [3]

व्याख्या:-

- राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वोट का मूल्य वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है। राजस्थान के विधायक के वोट का मूल्य 129 है।
- वर्ष 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 थी।

18. निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गयी?

- (1) राज्य विधान सभा
(2) संविधान सभा
(3) राज्य पुनर्गठन आयोग
(4) राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न [3]

व्याख्या:-

- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गयी।
- राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर, 1953 में की गई थी।

19. किस संशोधन अधिनियम द्वारा 'ग्राम सेवक' को 'ग्राम विकास अधिकारी' से प्रतिस्थापित किया गया है?

- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
(2) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2017
(3) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019
(4) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021
(5) अनुत्तरित प्रश्न [4]

व्याख्या:-

- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा 'ग्राम सेवक' को 'ग्राम विकास अधिकारी' से प्रतिस्थापित किया गया है।
- इस संशोधन के द्वारा कहा गया है कि 'ग्राम विकास अधिकारी' की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति 'ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता/ग्राम सेवक' के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

20. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- (i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं।

(ii) आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाये जा सकते हैं।

- (1) न तो (i) न ही (ii) सही है।
(2) (i) व (ii) दोनों सही हैं।
(3) केवल (ii) सही है।
(4) केवल (i) सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न [2]

व्याख्या:-

- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है।
- संविधान के भाग-XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी से संबंधित उपबंध है।

21. तहसीलदार की नियुक्ति होती है-

- (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
(2) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
(4) राजस्व मण्डल द्वारा
(5) अनुत्तरित प्रश्न [4]

व्याख्या:-

- तहसीलदार तहसील के सभी भूमि और राजस्व रिकॉर्ड को बनाए रखने तथा उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है।
- राजस्थान में तहसीलदार के पद हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के द्वारा किया जाता है।

22. 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है?

- (1) पंचायती राज (2) मानवाधिकार
(3) राज्यपाल (4) लोकायुक्त
(5) अनुत्तरित प्रश्न [4]

व्याख्या:-

- 2014 में महाधिवक्ता श्री नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति लोकायुक्त विषय से संबंधित है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1973 में बने लोकायुक्त अधिनियम में समय की माँग के अनुरूप प्रभावी संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गयी व इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 28 फरवरी, 2014 को मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर अधिनियम को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था।

23. राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिये-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 ट के अधीन जुलाई, 1994 में इसका गठन किया गया।
(ii) राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है।
(1) न तो (i) न ही (ii) सही है।

2021

- (2) (i) व (ii) दोनों सही हैं।
 (3) केवल (ii) सही है।
 (4) केवल (i) सही है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

[2]

व्याख्या:-

- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई, 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट (243K) के तहत किया गया था। यह एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं।
- राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव सम्पन्न कराता है।

24. अप्रैल, 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है?

- (1) अजमेर में (2) कोटा में
 (3) जोधपुर में (4) उदयपुर
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

[3]

व्याख्या:-

- अप्रैल, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी थी।
- यह राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह करेगी।
- राजस्थान सरकार के बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप की गई थी।

25. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिये-

- (i) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य हैं।
 (ii) वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं।

- (1) न तो (i) न ही (ii) सही है।
 (2) (i) व (ii) दोनों सही हैं।
 (3) केवल (ii) सही है।
 (4) केवल (i) सही है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

[3]

व्याख्या:-

- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में श्री गंगा राम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।

26. राज्य विधान परिषद् के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।
 (2) केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
 (3) राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।
 (4) केन्द्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।

[2]

व्याख्या:-

- केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे।

27. राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन-से विभाग के प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति 'क' के नियंत्रणाधीन नहीं है?

- (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग (2) गृह विभाग
 (3) शिक्षा विभाग (4) वित्त विभाग

[2]

व्याख्या:-

- राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार गृह विभाग के प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति 'क' के नियंत्रणाधीन नहीं है जबकि शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग नियंत्रणाधीन है।

28. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है -

- (1) विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष
 (2) राष्ट्रपति के समक्ष
 (3) राज्यपाल के समक्ष
 (4) मुख्य सचिव के समक्ष

[3]

व्याख्या:-

- राजस्थान लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

29. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं?

- (1) 10 (2) 12
 (3) 8 (4) 6

[3]

व्याख्या:-

- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद् में अधिकतम 8 व्यक्तियों को निर्देशित किया जा सकता है।

30. निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्त्व में कौन सम्मिलित नहीं है?

- (1) विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण

- (2) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना
(3) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा
(4) अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान [4]

व्याख्या:-

- **नागरिक अधिकार पत्र सम्मिलित तत्त्व:** अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें दी जाने वाली सेवाओं का विवरण
(1) विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण
(2) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना
(3) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा
- नागरिकों या बाहरी संस्थाओं द्वारा विभागीय कार्य के 'निरीक्षण (Inspection) का प्रावधान' इसके मूल घटकों में नहीं आता।

31. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी?

- (1) 2021 (2) 2013
(3) 2009 (4) 2018 [3]

व्याख्या:-

- 2009 में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी को जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया।
- राज्य कैडर के कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हुए सरकार ने विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की स्थापना तथा समयबद्ध पदोन्नति की नीति पेश करके संभावनाओं में सुधार के लिए कदम उठाया।

32. राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं?

- (A) हरिदेव जोशी (B) भैरों सिंह शेखावत
(C) टीकाराम पालीवाल (D) बरकतुल्लाह खान
सही उत्तर है -

- (1) (A), (B), (C) और (D) (2) केवल (A) और (B)
(3) केवल (B), (C) और (D) (4) केवल (A), (B) और (D) [4]

व्याख्या:-

- हरिदेव जोशी - बाँसवाड़ा विधानसभा
- भैरों सिंह शेखावत - छाबड़ा विधानसभा
- बरकतुल्लाह खान - तिजारा विधानसभा
- टीकाराम पालीवाल - 1962 में हिंडौन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए।

33. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है?

- (1) मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी
(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(3) प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति
(4) पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी [2]

व्याख्या:-

- राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और सदस्यों को कम से कम सात साल के अनुभव के साथ राज्य में उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश होना चाहिए।

34. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति' को प्रतिस्थापित किया गया है?

- (1) 88 (2) 89
(3) 91 (4) 90 [2]

व्याख्या:-

- 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 89 को संशोधन- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 89 की उपधारा (b) में - (क) खण्ड (a) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'ग्राम सेवक' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'ग्राम विकास अधिकारी' प्रति स्थापित की जाएगी।

35. राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही है?

- (1) वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
(2) उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है।
(3) वह भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन के मामलों पर विचार करता है।
(4) उसका कार्य आरोपों की जाँच करना है, न कि शिकायतों की।

कूट :

- (1) (A) एवं (C) (2) (A) एवं (D)
(3) (A), (B) एवं (C) (4) (A), (B), (C) एवं (D) [*]

व्याख्या:-

- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

36. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए-

- (i) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का गठन दिसम्बर, 1994 में हुआ।
(ii) इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।

कूट :

- (1) केवल (i) सही है
(2) केवल (ii) सही है
(3) (i) और (ii) दोनों सही हैं
(4) न तो (i) और न ही (ii) सही है [2]

व्याख्या:-

राज्य निर्वाचन आयोग

- यह संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग-9 अनुच्छेद-243K(z) में मिलता है।

- 73वें संविधान संशोधन के तहत जून, 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया (कार्य शुरू जुलाई, 1994)
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों व पदावधि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा नियम बनाकर किया जाता है।
- इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी भी होता है।
- राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो यह प्रावधान तीसरे निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत खन्ना से लागू हुआ।

37. गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था-

- (1) 2 नवम्बर, 1956 को (2) 25 अक्टूबर, 1956 को
(3) 1 नवम्बर, 1956 को (4) 26 अक्टूबर, 1956 को

[2]

व्याख्या:-

- 25 अक्टूबर, 1956 गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवम्बर, 1956 को पद भार संभाला तथा 15 अप्रैल, 1962 तक इस पद पर आसीन रहे।

38. राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं?

- (1) जस्टिस मोहम्मद यामीन
(2) जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया
(3) जस्टिस फारूख हसन
(4) जस्टिस यादराम मीणा

[3]

व्याख्या:-

- जस्टिस फारूख हसन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1985-1994 तक थे। इन्होंने राजस्थान सरकार ने राज्यमंत्री का पद भी संभाला।

2018

39. निम्नांकित में से कौन-सा अधिनियम/नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है?

- (1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996
(3) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों) का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999
(4) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011

[4]

व्याख्या:-

- राजस्थान ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली के तहत राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में रूपांतरण) नियम, 2011 अधिनियम के तहत राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है।

40. निम्नांकित में से कौन-से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं?

- (अ) हरिदेव जोशी (ब) शिवचरण माथुर
(स) अशोक गहलोत (द) वसुंधरा राजे
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

- (1) (अ), (ब) और (स) (2) (ब) और (स)
(3) (स), और (द) (4) (अ) और (द)

[2]

व्याख्या:-

- शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी सदन के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं।

41. निम्न में से किन पदाधिकारी/पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त, राजस्थान द्वारा जाँच नहीं की जा सकती है?

- (1) पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप-प्रधान
(2) पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
(3) सरपंच एवं पंच
(4) जिला परिषद् का उप-प्रमुख

[3]

व्याख्या:-

- लोकायुक्त के दायरे के बाहर-

- (1) मुख्यमंत्री
(2) महालेखाकार
(3) आर. पी. एस. सी. चैयरमैन व सदस्य
(4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(5) राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी (6) राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
(7) उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश
(8) सेवानिवृत्त लोकसेवक
(9) सरपंचों, पंचों, विधायकों आदि।

42. निम्नांकित में से कौन-से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्बन्ध में सही हैं?

- (अ) इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी, 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ।
(ब) यह आयोग मार्च, 2000 से क्रियाशील हुआ।
(स) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है।
(द) इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

- कूट-
(1) केवल (अ), (ब) और (स)
(2) केवल (अ), (ब) और (द)
(3) केवल (ब), (स), (द)
(4) केवल (ब), और (स)

[2]

व्याख्या:-

- 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत किया गया।
- इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 में संशोधन करके आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों का प्रावधान किया गया।
- आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है।

43. उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं?

- (1) न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल
- (2) न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान
- (3) न्यायमूर्ति ए. के. माथुर
- (4) न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी

[4]

व्याख्या:-

- राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न मुख्य न्यायाधीश रहे-**
प्रथम के. के. वर्मा
न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल
न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान
न्यायमूर्ति ए. के. माथुर
ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (वर्तमान)

44. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं?

- (1) पूनम चंद विश्वाँई
- (2) निरंजन नाथ आचार्य
- (3) शांतिलाल चपलोत
- (4) परसराम मदेरणा

[1]

व्याख्या:-

- राजस्थान विधानसभा में 1980-85 तक पूनमचंद विश्वाँई ने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर काम किया।
- 1967 में पूनमचंद विश्वाँई ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया।
- 1967 से 1971 तक वे विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे।

45. राजस्थान विधानसभा में 'लोक महत्त्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव' की प्रक्रिया के नियम के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?

- (अ) प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है।
- (ब) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।
- (स) प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा।

(द) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

कूट-

- (1) केवल (अ), (ब) और (स)
- (2) केवल (अ), (ब) और (द)
- (3) केवल (अ), (स), और (द)
- (4) केवल (अ) और (द)

[3]

व्याख्या:-

- राजस्थान विधानसभा में "लोक महत्त्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव" की प्रक्रिया के नियमानुसार-

- (1) प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है।
- (2) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना से संबंधित विषय तक ही सीमित रहेगा।
- (3) एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे।
- (4) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

46. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबन्ध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, अब-

- (1) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।
- (2) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है
- (3) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेज देगा।
- (4) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।

[1]

व्याख्या:-

- राज्यपाल अनुमति देता है, तब वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कुछ विधेयकों को सदन में रखने से पूर्व अनिवार्य रूप से राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।

2016

47. राजस्थान राज्य में 30 जून, 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है?

- (1) 5 बार
- (2) 3 बार
- (3) 6 बार
- (4) 4 बार

[4]

व्याख्या:-

राजस्थान में आपातकाल

वर्ष	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	समय
1967	सरदार हुकुम सिंह	मोहन लाल सुखाड़िया	44 दिन
1977	रघुकुल तिलक	हरिदेव जोशी	54 दिन
1980	रघुकुल तिलक	भैरोंसिंह शेखावत	111 दिन
1992	डॉ. एम. चन्नारेड्डी	भैरोंसिंह शेखावत	354 दिन

48. सन् 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी?

- (1) 200
- (2) 160
- (3) 188
- (4) प्रत्येक जिले में तीन विधायक

[2]

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान के अनु. 81 तथा 170 में क्रमशः संसद और राज्यों के सदनों की अधिकतम सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है।
 - अब तक चार बार (1952, 1962, 1972, 2002) परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।
 - वर्तमान सीटों का निर्धारण 2002 के परिसीमन आयोग के तहत किया गया है जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा।
 - 1952 के परिसीमन आयोग के तहत राजस्थान विधानसभा में 160 सीटें थी तथा वर्ष 2002 के परिसीमन आयोग में 200 सीटों का प्रावधान किया गया।
 - अनु. 330 में संसद तथा राज्य विधानमण्डलों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु आरक्षित सीटों का प्रावधान वर्तमान में लोकसभा में ST-47, SC-84 सीटें आरक्षित है।
- 49. राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व, निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे?**

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) ओ. पी. कोहली | (2) रामनरेश यादव |
| (3) राम नायक | (4) मागरिट अल्वा |
- [3]**

व्याख्या:-

- कल्याण सिंह राजस्थान के 22वें राज्यपाल (2014- 2019) रहे।
- कल्याण सिंह से पूर्व राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रामनायक थे।

राजस्थान के राज्यपालों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (1956- 1962) सर्वाधिक समय तक
- प्रथम महिला राज्यपाल- प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2004- 2007)
- पद पर रहते हुए मृत्यु- निर्मल चन्द्र जैन, शेलेन्द्र सिंह, प्रभाराव
- वर्तमान राज्यपाल **कलराज मिश्र** है।

50. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (1) मोहम्मद याकूब | (2) यतीन्द्र सिंह |
| (3) डी. एस. तिवाड़ी | (4) सी. आर. चौधरी |
- [3]**

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान के अनु. 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग प्रावधान है।

राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त, 1949
- प्रथम अध्यक्ष डॉ. एस. के. घोष
- वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय
- सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डी. एस. तिवाड़ी (1951-1958) का रहा।
- अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष / 62 वर्ष
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात सदस्यों (कुल-8 सदस्य) की नियुक्ति का प्रावधान।
- नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, हटाना- राष्ट्रपति द्वारा।

51. जिला आयोजन समिति के निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं?

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) 20 और 5 | (2) 20 और 3 |
| (3) 20 और 2 | (4) 20 और 10 |
- [2]**

व्याख्या:-

- भारतीय 'संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत जिला आयोजन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 20 निर्वाचित तथा 3 पदेन सदस्य होते हैं।
- इसका अध्यक्ष जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) होता है।

52. जिला दण्डनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं-

- (A) कानून व व्यवस्था बनाए रखना
(B) पुलिस पर नियंत्रण रखना।
(C) विदेशियों के पारपत्रों की जाँच करना।
(D) भू-राजस्व एकत्र करना।

कूट :

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) A, B तथा C | (2) A, C तथा D |
| (3) B, C तथा D | (4) A, B तथा D |
- [1]**

व्याख्या:-

- जिला दण्डनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ निम्न है-
- कानून व व्यवस्था बनाए रखना
- पुलिस पर नियंत्रण रखना।
- विदेशियों के पारपत्रों की जाँच करना।

53. सही उत्तर चुनें-

राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं-

- (1) सभी राज्य विश्वविद्यालयों के
(2) सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के
(3) सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के
(4) सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के
- [1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कुलपति अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को पहुँचाता है।

54. राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था-?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) 18 अप्रैल, 2008 | (2) 18 अप्रैल, 2006 |
| (3) 18 अप्रैल, 2007 | (4) 18 अप्रैल, 2005 |
- [2]**

व्याख्या:-

राजस्थान सूचना आयोग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य

- राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल, 2006
- राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त - एम.डी. कोरानी
- संगठन- मुख्य आयुक्त + 10 अन्य आयुक्त (कुल सदस्य - 11)

- पदावधि- राज्य द्वारा निर्धारित 3 वर्ष सेवा काल या 65 वर्ष आयु जो पहले हो
- शपथ तथा त्यागपत्र- राज्यपाल द्वारा
- वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त देवेन्द्र भूषण गुप्ता

55. सही उत्तर चुनें-

राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी?

- (1) राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति
- (2) भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)
- (3) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
- (4) सन्धानम समिति

[2]

व्याख्या:-

- भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-08) ने ई-गवर्नेन्स की अनुशंसा की थी।
- सन्धानम समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया।

56. सही विकल्प चुनें-

दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिये संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

- (1) सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा
- (2) भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
- (3) सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा
- (4) संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा

[2]

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान के अनु. 315-323 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।
- इनके अध्यक्ष की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा सम्बन्धित राज्य की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
- कार्यकाल- 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

57. राजस्थान विधान सभा के इतिहास में 30 जून, 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई?

- (1) एक बार
- (2) दो बार
- (3) तीन बार
- (4) चार बार

[4]

व्याख्या:-

राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव का इतिहास-

क्र.सं	समय	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
I	23 मार्च, 1990	भैरोसिंह शेखावत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
II	30 नवंबर, 1990	भैरोसिंह शेखावत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
III	31 दिसम्बर, 1993	भैरोसिंह शेखावत	बलिराम भगत
IV	3 जून, 2009	अशोक गहलोत	प्रभाराव

V	13 अगस्त, 2020	अशोक गहलोत	कलराज मिश्र
---	----------------	------------	-------------

58. सही उत्तर दें:

राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है-

- (1) एक वैधानिक संस्था
- (2) एक कार्यपालिका संस्था
- (3) एक संवैधानिक संस्था
- (4) भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई बीए

[3]

व्याख्या:-

- भारतीय संविधान में अनु. 243 K तथा अनु. 243 ZA के तहत राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष 1994 में किया गया था।
- राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का एक स्वतंत्र, स्वायत्त व संवैधानिक निकाय है।
- 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- प्रथम अध्यक्ष - अमर सिंह राठौड़
- वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है- मधुकर गुप्ता

59. वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं?

- (1) 5 बार
- (2) 8 बार
- (3) 9 बार
- (4) 10 बार

[4]

व्याख्या:-

- भारत में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव से किया गया था। पंचायत के लिए पहले चुनाव वर्ष 1959 में हुए थे।
- राजस्थान ने वर्ष 1993 में पंचायत अधिनियम बनाया था तथा ग्राम पंचायतें स्थापित की थीं। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल, को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस मनाया जाता है।
- वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के 10 बार आयोजित किए गये।

60. जनसमस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है?

- (1) लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम
- (2) लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम
- (3) सुशासन अधिनियम
- (4) सुनवाई का अधिकार अधिनियम

[4]

व्याख्या:-

- राजस्थान देश का पहला राज्य जन सामान्य की लोक शिकायतों और समस्याओं के समुचित और समयबद्ध निस्तारण हेतु 1 अगस्त, 2012 को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया।

2015

61. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था?

- (1) जस्टिस एन. के. जैन
- (2) जस्टिस एस. सगीर अहमद
- (3) जस्टिस कान्ता भटनागर
- (4) जस्टिस प्रेमचंद जैन

[4]

व्याख्या:-

- वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री महेशचंद्र शर्मा हैं।
- प्रथम अध्यक्ष – जस्टिस कान्ता भटनागर
- द्वितीय अध्यक्ष – एन. के. जैन
- तृतीय अध्यक्ष – एस. सागीर अहमद
- वर्तमान अध्यक्ष – गोपाल कृष्ण व्यास

62. कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारण्टी डिलिवरी अधिनियम, 2011 में गारण्टी दी गई-

- (1) 106
- (2) 107
- (3) 108
- (4) 109

[*]

व्याख्या:-

- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

63. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर थी-

- (1) 75.19 प्रतिशत
- (2) 76.19 प्रतिशत
- (3) 77.19 प्रतिशत
- (4) 78.19 प्रतिशत

[2]

व्याख्या:-

- राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर 76.19 प्रतिशत थी।

64. राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था-

- (1) भारतीय संसद
- (2) राम राज्य परिषद्
- (3) किसान मजदूर प्रजा पार्टी
- (4) हिन्दू महासभा

[2]

व्याख्या:-

- स्वतंत्रता के बाद राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद राम राज्य परिषद् को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था।

- कांग्रेस को 82 तथा राम राज्य परिषद् को 24 सीटें प्राप्त हुई थी।

- राजस्थान में प्रथम विधानसभा में कुल 160 सीटें थी।

65. किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था?

- (1) 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित
- (2) 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित
- (3) 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित
- (4) 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित

[4]

व्याख्या:-

- राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। अप्रैल, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।

- 15 जनवरी, 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारम्भ की।

66. राजस्थान सरकार मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है?

- A. आयोग ने मई, 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया।
- B. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं।
- C. आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं।
- D. जुलाई, 2000 से जुलाई, 2005 तक न्यायाधीश ए. एस. गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे।

नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

- (1) A, C और D
- (2) B, C और D
- (3) B और C
- (4) A, B, C और D

[1]

व्याख्या:-

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मई, 2000 से पूर्णतया: कार्य करना शुरू किया तथा इसकी पहली अध्यक्ष जस्टिस कान्ता भटनागर (2000) थीं। इसके वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं।

67. सूची-I (14वीं राजस्थान विधान सभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियाँ) को सूची-II (उनके अध्यक्ष) से सुमेलित कीजिए-

सूची-I समिति

- A. लोक लेखा समिति
- B. लोक उपक्रम समिति
- C. प्राक्कलन समिति
- D. प्राक्कलन ख समिति

सूची-II उनके अध्यक्ष

- I. मोहनलाल गुप्ता
- II. ज्ञानदेव आहुजा
- III. प्रद्युम्न सिंह
- IV. डॉ. गोपाल कृष्ण

कूट-

- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|-----|
| (1) | III | I | II | IV |
| (2) | I | III | IV | II |
| (3) | IV | II | I | III |
| (4) | III | IV | I | II |

[1]

व्याख्या:-

अध्यक्ष

समिति

- लोक लेखा समिति
लोक उपक्रम समिति
प्राक्कलन समिति 'क'
प्राक्कलन समिति 'ख'

2017-18

- प्रद्युम्न सिंह
मोहनलाल गुप्ता
ज्ञानदेव आहुजा
डॉ. गोपाल कृष्ण

68. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया?

- (1) 6
- (2) 4
- (3) 7
- (4) 2

[2]

व्याख्या:-

- राजस्थान में अब तक चार बार (1968, 1977, 1980, 1992) राष्ट्रपति शासन लग चुका है।

69. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का प्रमुख सचिव बना?

- (1) श्री बी. जी. राव (2) श्री वी. नारायण
(3) श्री के. राधाकृष्णन (4) श्री एस. डब्ल्यू. शिवेश्वर

[3]

व्याख्या:-

- वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख सचिव उषा शर्मा हैं। श्री के. राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। सबसे लंबा कार्यकाल अभय सिंह मेहता का रहा था।

70. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च, 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है

1. उनके घरों में शौचालय होना चाहिए।
 2. जिला परिषद् की सदस्यता के लिए बी.ए. की डिग्री आवश्यक है।
 3. पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
 4. सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- (1) 1 और 2 सही हैं। (2) 2, 3 और 4 सही हैं।
(3) 1, 3 और 4 सही हैं। (4) 2 और 4 सही हैं। [3]

व्याख्या:-

- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च, 2015 को पारित किया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है कि उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, पंचायत समिति की सदस्यता के लिए दसवीं कक्षा पास होना और सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का पाँचवीं कक्षा पास होना आवश्यक है। वर्तमान सरकार द्वारा पंचायती राज में उक्त शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।